16.28 hrs.

RESOLUTION RE: ABOLITION OF RAJYA SABHA

श्री विभूति मिश्र: (मोतिहारी) : चेयरमैन साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं—

> "यह सभा सरकार को निदेश देती है कि वह राज्य सभा के उत्सादन का उपबन्ध करने के लिये संविधान का संशोधन करने हेतु एक विधेयक प्रस्तुत करे ।"

इस प्रस्ताव को लाने के लिये मैंने बहुत पहले प्रयत्न किया था, एक बिल लाया था, लेकिन उस बिल को अस्वीकार किया गया, उसके बाद यह दूसरा प्रस्ताव मैं लाया हूं । इस प्रस्ताव को पेश करने के पीछे मेरी बिलकुल विशुद्ध भावना है, इस हाउस से या उस हाउस के किसी भी सदस्य के प्रति कोई ईर्ष्या की भावना नहीं है । मेरा यह प्रस्ताव एकदम देश हित में है, इसलिये इस प्रस्ताव को यहां पेश कर रहा हूं ।

16.29 hrs.

[SHRI S. A. KADAR *in the Chair.*]

बात यह है कि हम लोगों ने अंग्रेजी राज्य के खिलाफ़ लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़कर हिन्दुस्तान को खण्डित रूप में स्वाधीन किया । हिन्दुस्तान के स्वाधीन हो जाने के बाद यहां एक कांस्टीचूएन्ट असेम्बली बनी और उसने हिन्दुस्तान का संविधान बनाया । उस समय जो कांस्टीचूएन्ट असेम्बली बनी, वह पूरे हिन्दुस्तान का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती थी, क्योंकि उस समय जो असेम्बली थी, उस असेम्बली का गठन इसलिये हुआ था कि अंग्रेज चाहते थे कि हम लोगों को फंसा कर रख और हम लोग उसमें इसलिये जाते थे कि अंग्रेजों से लड़ाई लड़नी थी । अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के लिये हम उस समय असेम्बली में गये और जब हिन्दुस्तान स्वाधीन हुआ तो उसी असेम्बली के जरिये विभिन्न प्रदेशों से प्रतिनिधि चुन कर आये जिन्होंने कांस्टीचूएन्ट असेम्बली का निर्माण किया और उस कांस्टीचूएन्ट असेम्बली में जो लोग गये थे, वे वह लोग थे जो अंग्रेजी राज्य के प्रभाव से प्रभावित थे, इंग्लैंड में पढ़े लिखे थे, यहां भी पढ़े थे, लेकिन अंग्रेजों की शिक्षा-दीक्षा से प्रभावित थे । इसलिये उन्होंने यह संविधान बनाया और यहां पर दो कमरे रखे—एक लोक सभा और दूसरी राज्य सभा । तो उस समय जो विधान बना उसमें एक लोक सभा बनी और दूसरी राज्य सभा बनी । लोक सभा के सदस्यों की तादाद है 523 और राज्य सभा के सदस्यों की तादाद है 240 के लगभग । मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1931 में गांधीजी फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी के सामने अपना बयान दे रहे थे तो उन्होंने क्या कहा था । उन्होंने कहा था कि केवल एक हाउस होना चाहिए, दो नहीं होने चाहिए । जो हमारे राष्ट्रपिता थे जिनके जरिए से हिन्दुस्तान में स्वाधीनता आई उन्होंने क्या कहा था वह मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं:

> "I am certainly not enamoured of I do not swear by two legislatures. I have no fear of a popular legislature running away with itself and hastily passing some laws of which afterwards it will have to repent. I would not like to give a bad name to it and then hang the popular legislature. I think that a popular legislature can take care of itself and since we are dealing with the poorest country in the world, the less expenses we have to bear, the better it is for us. I do not for one moment endorse the idea that unless we have an Upper Chamber to exercise control over the popular chamber, the popular chamber will ruin the country. I have no such fear, but I can visualise a state of affairs when there can be battle royal between the popular chamber and the Upper

Chamber. "(What Mahatmaji predicted has already come true and we have had so many battles royal with the other House)." Anyway, whilst I would not take up a decisive attitude in connection with it, personally I am of opinion that we can do with one Chamber only and that we can do with great advantage. We will certainly save a great deal of expenses if we can bring ourselves to believe that we shall do with one Chamber."

फिर गांधी जी ने कहा कि हमें अपना प्रिमिडेन्स कायम करना चाहिए, हमें इंग्लैंड को फालो नहीं करना चाहिए । उसमें उन्होंने कहा :

"We need not go after precedents. Let India create her own precedent, so that the rest of the world may follow it."

यह गांधीजी का कहना है जिनके झंडे के नीचे हम लोगों ने काम किया और स्वाधीनता प्राप्त की ।

इसी तरह से 1936 में पं० जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हिन्दुस्तान में केवल एक सदन होना चाहिए । इस तरह से आप देखेंगे कि दो माननीय नेताओं, गांधी जी और नेहरूजी ने कहा था कि हिन्दुस्तान में केवल एक ही हाउस होना चाहिए । इसके अलावा आप देखेंगे कि यह जो हाउस बना है उसको अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोगों ने बनाया था । मैंने आपके सामने गांधीजी का कोटेशन दिया और नेहरूजी का कोटेशन दिया उसके बाद आप देखें कि जो हिन्दुस्तान के लोग हैं उनको उस सदन की कहां तक जरूरत है ।

अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1954 में इस सदन में श्री गुरुपद स्वामी एक प्रस्ताव लाए थे और उसमें यह बात हुई थी कि दो हाउसेज होने से क्या फायदा है । मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 25 साल में, जो एक डाउरी का कानून था उसपर एक बार हम लोगों की संयुक्त बैठक हुई थी और उसके बाद और कोई हेर फेर नहीं हुआ है । इस तरह से हमारी केवल एक संयुक्त बैठक हुई, कोई दूसरी नहीं हुई । जो यहां पर होता है वही पास हो जाता है । आगे चलकर मैं यह भी बताऊंगा कि किस किस हाउस में कितना कितना खर्चा होता है और तब आपको पता चलेगा कि दो हाउसेज की जरूरत नहीं है ।

एक बात मैं यह भी बताना चाहता हूं कि वह जो दूसरा हाउस है उसमें ऐसे लोग आ जाते हैं जोकि चुनाव में हार गए । हमारी ही पार्टी की तरफ से अगर किसी को ओब्लाइज करना होता है तो वह आ जाते हैं । इसलिए वह नहीं आते हैं कि उनकी कोई उपयोगिता है बल्कि इसलिए कि उनको जगह देनी है । केवल हमारी पार्टी ही नहीं बल्कि और भी जो दूसरी पार्टीज हैं वह भी यही काम कर रही हैं । ऐसे भी लोग आ जाते हैं जोकि कभी भी जीवन में चुनाव का सामना नहीं करते, जो कभी भी जनता का मुकाबला नहीं करते । दूसरी तरफ हम लोग हैं जो चुनाव लड़कर आते हैं । हमको अपने क्षेत्र में घूमना पड़ता है, जनता से सम्पर्क रखना पड़ता है और उनकी हर तरह से सेवा करनी पड़ती है । हम लोग जनता के दुखदर्द को जानते हैं । दूसरी तरफ उन लोगों को जनता के दुखदर्द का कोई पता नहीं रहता । बिहार से 21 मेम्बर आते हैं वहां लेकिन हमारे जिले में शायद ही किसी ने कभी दर्शन दिये हों । इसलिए सभापति जी आप भी इस बात को सोचें, क्योंकि आप सदस्य भी हैं और चेयरमैन भी हैं कि पिछले 25 सालों में क्या हुआ ।

इसके अलावा एक बात यह भी है कि यह बैकडोर वाला सिस्टम गलत है । कोई आदमी चुनाव का सामना न करे और बैकडोर से चला आवे तो वह भी गलत है ।

[श्री विभूति मिश्र]

हम लोग यहां पर चुनाव लड़कर आते हैं पांच साल के लिए लेकिन उसमें भी खतरा रहता है कि पता नहीं कब लोकसभा डिजाल्व हो जाये लेकिन उस हाउस में 6 साल तक कोई खतरा ही नहीं है। हमारे लाखों वोटर्स हैं जिनके पीछे घूमते घूमते हम परेशान रहते हैं और दूसरी तरफ उस हाउस के सदस्य 30, 40 या 50 वोटर्स से चुनकर आ जाते हैं। मैं किसी तरह का एस्पर्शन नहीं कर रहा हूं लेकिन 40 या 50 वोटर्स के वोट यदि हम चाहें तो किसी न किसी उपाय से ले सकते हैं और यह बात आप सभी को मालूम भी है। इसलिए हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में सीधे रूप से सरकार चले। गांधीजी ने जो कहा था उसको हमने नहीं माना। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि उस हाउस को जो राज्य सभा के नाम से प्रचलित है उसको सरकार हटा दे। यह सरकार कहती है कि हम प्रोग्रेसिव हैं लेकिन मैं पूछना चाहता हूं किस प्रकार से हैं। पहले राजा होते थे उनके यहां सभासद रहते थे और वह भी राजा से लड़ाई करते थे। इंग्लैंड का यही इतिहास है कि जब चार्ल्स I को फांसी हो गई तो हाउस आफ कामन्स को अधिकार मिले जबकि कामवेल का राज्य आया लेकिन जब कामवेल का राज्य ढीला हो गया तो फिर हाउस आफ लार्डस आ गया।

SHRI SEZHIYAN (Kumbakonam): On a point of order. This is a very important discussion pertaining to a part of Parliament. It is but proper that the Minister in charge who will reply to the debate should be present in the House.

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI KEDAR NATH SINGH): I am taking notes on his behalf. He is coming in a few minutes.

SHRI SEZHIYAN: This is disrespect to the House which is seized of the matter. This is a very serious matter.

SHRI KEDAR NATH SINGH: He has gone with the permission of the Chair.

MR. CHAIRMAN: He is returning.

श्री विभूति मिश्र : अब हमारी पार्टी का राज्य है लेकिन हम महसूस करते हैं कि कुछ ऐसी मनोवृत्ति वाले लोग हैं जो यह चाहते हैं कि बड़ों का ही राज्य बना रहे। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इस बात को माने। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि एक हाउस से क्या फायदे हैं। एक हाउस होने से फायदा यह है कि किसी काम पर जल्दी से जल्दी कार्यवाही हो सकती है। दूसरी बात यह है कि उस काम में कोई आब्स्ट्रक्शन नहीं होता। तीसरी बात यह है कि कैबिनैट इसी हाउस के प्रति जवाब देह रहेगी। इसी हाउस के चुने हुए लोगों की कैबिनैट होगी और वह हमारे सामने ही जवाब देह रहेगी। हम चाहे विरोध करेंगे या समर्थन करेंगे, जैसा जो परिस्थिति होगी वैसा करेंगे। चौथी बात यह है कि डुप्लीकेशन नहीं होता है कि पहले यहां से हो और फिर वहां जाये। एक हाउस में काम हो गया तो सरकार का काम चलने लगा। इसके अलावा कोई झगड़ा नहीं रहेगा। आज कभी कभी किसी बात को लेकर दोनों सदनों के अधिकारों पर झगड़ा हो जाता है। जब एक ही हाउस रहेगा इस प्रकार के झगड़े की कोई संभावना नहीं रहेगी। इसलिए जरूरी है कि एक हाउस हो रहे।

"The second chamber which usually claims to be conservative is in a position to impede reforms and all such progressive measures."

आप को याद होगा कि पिछले सेशन में जब प्रिवी पर्स का बिल आया तो यहां से पास हो गया लेकिन राज्य सभा में एक बटे तीन वोट की कमी से गिर गया। और फिर उसके बाद चुनाव हुआ और फिर

यहां से पास हुआ तब उस हाउस में लोगों ने समझा कि अब हमारा बहुमत होने जा रहा है तब उस हाउस के लोगों को बुद्धि आई और वह बिल पास हुआ । इससे स्पष्ट होता है कि जितने प्रोग्रेसिव मेजर्स यहां से लिए जाते हैं उनको वह हाउस रोक देता है। कुछ लोग गांधीजी के बारे में कहते हैं कि वह अनप्रोग्रेसिव थे । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने 1931 में कहा था कि एक हाउस रहना चाहिए । आप देखिये 42 साल पहले उनके कितने प्रोग्रेसिव विचार थे ।

मेरा विचार है कि दूसरे हाउस के रखने से कोई उन्नतिशील काम हम नहीं कर सकते । हमको जरूरत पड़ जाती है कि राज्य सभा से पास करायें, राज्य सभा में जायें । यहां से पास नहीं होता तो राज्य सभा में बिल नहीं जाएगा । इसलिए उस हाउस की कोई जरूत नहीं है, उससे देश की तरक्की में बाधा पड़ रही है । मैं श्री नीति राज चौधरी से कहूंगा कि वह ऐसा कानून लायें । प्रधान मंत्री होती तो और अच्छा होता क्योंकि उनके पिता स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि दो हाउस नहीं रहने चाहिए । आज जब हम स्वतन्त्रता की स्वर्ण जयन्ती मना रहे हैं इसमें यह काम होना चाहिए कि दो हाउस की जगह एक हाउस रहे और राज्य सभा को हटा दिया जाये ।

आप देखिये कि हमारी बैठकें उनसे ज्यादा हुईं । 1952 में 61 दिन बैठक हुई राज्य सभा की और हमारी 123 दिन की बैठक हुई । 1953 में राज्य सभा की बैठक 100 दिन हुई, हमारी 137 दिन । 1954 में राज्य सभा की 103 दिन और हमारी 137 दिन, 1955 में उनकी 112 दिन की बैठकें हुई, हमारी 139 दिन बैठक हुई । 1956 में राज्य सभा की 114 दिन, लोक सभा की 151 दिन । 1957 में उनकी 78 दिन, हमारी 106 दिन, 1958 में उनकी 90 दिन हमारी 125 दिन, 1959 में हमारी 187 दिन, उनकी 23 दिन की । 1960 में उनकी बैठक 87 दिन की और हमारी 121 दिन, 1961 में उनकी 75 दिन और हमारी 102 दिन, 1962 में 91 दिन की बैठक राज्य सभा की और लोक सभा की 116 दिन, 1963 में राज्य सभा की 100 दिन, हमारी 122 दिन, 1964 में 97 दिन उनकी, 122 दिन की हमारी, 1965 में 96 दिन उनकी, 113 दिन की बैठक हमारी । 1966 में 109 दिन राज्य सभा की बैठक और हमारी 119 दिन । 1967 में राज्य सभा 91 दिन और हमारी 111, 1968 में 103 दिन राज्य सभा की बैठक और लोक सभा की बैठक 120 दिन । 1969 में 102 दिन राज्य सभा और 120 दिन लोक सभा । 1970 में 107 दिन राज्य सभा, 119 दिन लोक सभा, 1971 में 79 दिन राज्य सभा और लोक सभा को 102 दिन की बैठक, 1972 में उनकी 99 दिन की बैठक हुई और लोक सभा की 111 दिन की बैठक हुई ।

आप देखिये उनकी तादाद कितनी है और हमारी कितनी है । मैंने घंटों का हिसाब नहीं लगाया कि हम कितने घंटे बैठते हैं और राज्य सभा कितने घंटे बैठती है । लेकिन जाहिर है कि हम उन से ज्यादा घंटों तक बैठते हैं, कभी कभी तो रात के 9 बजे तक बैठते हैं । हम सीधे जनता से चुन कर आते हैं और राज्य सभा के सदस्यों को असेम्बली के सदस्य चुनते हैं, यानी वे जनता के प्रतिनिधि के प्रतिनिधि हैं ।

जरा खर्चे के आंकड़े देखिये ।

सभापति महोदय : चूंकि आप के पास वक्त कम है इसलिये संक्षेप में बता दीजिये ।

श्री विभूति मिश्र : ठीक है, मैं एक दो साल का पढ़े देता हूं। 1973 में हमारा खर्चे का तखमीना तीन करोड़ के करीब था जब कि उनका एक करोड़ 19 लाख के करीब था। 1972 में हमारा तखमीना 2 करोड़ 80 लाख के करीब था और राज्य सभा का 1 करोड़ 14 लाख के करीब था। 1971 में लोक सभा का 2 करोड़ 20 लाख था, राज्य सभा का 1 करोड़ 13 लाख था। खर्चा भी उन पर ज्यादा है, जब कि तादाद उनकी कम और काम के घंटे कम। इस गरीब मुल्क में इतने पैसे में हम छोटे छोटे साइफ़न नदियों पर बना सकते थे जिससे सिंचाई कर सकते थे।

राज्य सभा में बहुत धुरन्धर कार्यकर्ता हैं और बड़े योग्य पुरुष हैं। मेरी किसी के प्रति निरादर नहीं है। उसमें हमारे ही जैसे, बल्कि हम से ज्यादा त्यागी और तपस्वी सदस्य हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि वह इससे सहमत होंगे कि उस सभा की जरूरत नहीं है, कोई उपयोगिता उसकी नहीं है। और जब उपयोगिता नहीं है तो सरकार को बिला लिहाज के उसको समाप्त कर देना चाहिए।

कहा गया कि उस सदन में लिट्रेरी आदमी हैं। एक दार्शनिक लीकाक ने राजनीति की थ्योरी लिखी है कि जो आदमी चुनाव नहीं लड़ना चाहता उसके लिये कुछ ऐसा प्रोवीजन किया जाय। तो आप बजाय सदन के ऐसे लोगों का कोई कारपोरेशन बना दीजिये, जैसे इंजीनियरों का है। जैसे भारत के पुराने राजे महाराजे पंडितों का संगठन कर देते थे, उसी तरह से जो बड़े लिट्रेरी आदमी हैं, साइंटिस्ट हैं, उनका एक कारपोरेशन बना दें। सरकार अपने यहां उनको रखे और वजीफ़ा दे जिससे वह अपनी रिसर्च करते रहें। वहां रखने से मेरा खयाल है आप इस तरह के लिट्रेरी आदमियों के मिजाज को खराब करते हैं। यहां पहले श्री मेघनाथ साहा एक सदस्य थे, वह बड़े अच्छे आदमी थे। वह यहां हाउस में आते थे तो पंडितजी से उनकी टक्कर हो जाती थी। एक बार मुसोलिनी का नाम लिया तो पंडितजी ने कहा मेरे यहां मुसोलिनी आया था, मैंने उनकी बात नहीं मानी। इस पर वे चुप हो गये। वह बेचारे सेन्ट्रल हाल में बैठे किताब पढ़ते रहते थे। मैं समझता हूं ऐसे आदमियों को राजनीति में नहीं आना चाहिये। सेकेन्ड चैम्बर में राजनीति जानने वाले आदमियों से काम नहीं होगा। इसलिये जो लिट्रेरी, साइंटिस्ट और विशेषज्ञ हैं उनके लिये सरकार अलग प्रोवीजन कर दे।

12 आदमियों का सरकार चुनाव करती है, हर दो वर्ष में चार आदमी चुने जाते हैं। एक दलील यह दी जाती है कि हाउस डिजाल्व नहीं होता है। सही है। लेकिन जब लोक सभा डिजाल्व हो जाती है तो उस हाउस की क्या कीमत रह जाती है?

सभापति महोदय : अब 1 मिनट है आप के पास।

श्री विभूति मिश्र : लोक सभा डिजाल्व हो जाती है तो राज्य सभा की कोई कीमत नहीं रहती है। मैं कहता हूं कि सरकार को सुबुद्धि आनी चाहिये। यह हमारी सरकार है। गांधीजी ने कहा था, जवाहरलालजी ने कहा था इसके बारे में। आज दुनिया समाजवाद की तरफ आगे बढ़ रही है। दुनिया आगे बढ़ रही है। लेकिन आप इंग्लैंड की, अमरीकी की बात को पकड़े हुए हैं, उनके पद-चिन्हों पर चल रहे हैं। आप दुनिया में क्रान्ति चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? यदि क्रान्ति नहीं चाहते हैं तो बताएं कि जनता आपको क्या कहेगी? जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा चाहे वह इनकम टैक्स से आता हो, एक्साइज ड्यूटी से आता हो, कपड़ा जो गरीब आदमी पहनता है, एक धोती पहन कर साल भर अपना गुजारा करता है, उस धोती पर लगे टैक्स का पैसा

ले कर आप बरबाद करते हैं, यह उचित नहीं है । उस हाउस के किसी भी माननीय सदस्य के प्रति मेरी कोई बुरी भावना नहीं है । वे हम से ज्यादा तपस्वी और त्यागी है, इसको भी ईमानदारी से मानता हूं । लेकिन इस देश के हित में जनता ने जिनको चुन कर भेजा है आपका जो उत्तरदायित्व है उसको आपको निभाना चाहिये । मैंने इस सवाल पर बहुत सोचा है, बहुत विचार किया है और सोचने और विचारने के बाद ही मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस प्रस्ताव को ला कर उस हाउस के एबालिशन की मांग करूं ।

आप आगे बोलने नहीं देते हैं । अब जब मैं जवाब दूंगा तब देखूंगा ।

MR. CHAIRMAN: Resolution moved:

> "This House directs the Government to bring forward a Bill to amend the Consultation to provide for the abolution of Rajya Sabha."

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मुझे खुशी है कि एक बहुत ही पुराने मैम्बर इस प्रस्ताव को यहां लाए हैं । मैं समझता हूं कि उसूलन भी राज्य सभा खत्म होनी चाहिये । इसी सदन में हम लोग बंगाल काउंसिल को खत्म करने का बिल लाए थे । तब तकरीबन एक राय से वह पास भी हुआ था हालांकि कुछ लोगों ने उसकी मुखालफित की थी । मेरी यह खुशकिस्मती है कि मैं चौथी बार यहां जीत कर आया हूं । मैं कभी कभी सोचता हूं कि यदि के० के० बिड़ला कहीं चाहें राज्य सभा का चुनाव लड़ना जैसे वह लोक सभा का लड़े थे तो कोई भी ताकत हिन्दुस्तान में नहीं थी जो उनको हरा सकती । रुपये के बल पर वोट मिल जाते हैं । केवल 42 असैम्बली के मैम्बरों के वोट लेने की जरूरत पड़ती है । बड़े बड़े मौनोपोली हाउसिस के नुमाइंदे राज्य सभा में हैं, इसको भी आप मानते हैं । मैं कोई टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं । वहां हम से ज्यादा काबिल आदमी हो सकते हैं । उन्होंने भी कुर्बानियां की होंगी । लेकिन हमें सोचना है कि आज वाकई में क्या देश में राज्य सभा की जरूरत है ? गांधीजी का उदाहरण उन्होंने बताया है और जो कुछ उन्होंने कहा था उसको पढ़ कर आपको सुनाया है । मैं समझता हूं कि गांधीजी के आदर्शों को तो हम भूलते ही जा रहे हैं । वह अगर जिन्दा होते और इस सदन में आ जाते तो उनको कहां बिठाया जाता ? डिसटिंग्विश्ड विजिटर्ज गैलेरी में वह बैठ नहीं सकते थे क्योंकि लोक सभा के वह सदस्य नहीं रहे थे, आर्डिनरी गैलरी में हम उनको बिठा नहीं सकते थे । मेरे खयाल में प्रेस गैलरी में ही शायद वह बैठ सकते थे क्योंकि वह अखबार चलाते थे । गांधीजी के आदर्शों को हम भूलते जा रहे हैं । मैं चाहता हूं कि सरकार इस सब के बारे में संजीदगी से सोच विचार करे ।

सहूलियतों के बारे में कहा गया है । यहां हम जनता के पास जा कर इलैक्शन जीतते हैं और जीतने के बाद देखा गया है कि सुबह अगर हमें माला पहनाई जाती है तो शाम को गाली खाने की भी हम में हिम्मत होनी चाहिये । राज्य सभा के सदस्यों के सिलसिले में ऐसा कभी नहीं होता है । खास जिम्मेदारी उनकी नहीं है । जो सही राजनीति को मानते हैं और उस पर चलते हैं, उनकी यह जिम्मेदारी है । हमारे यहां भीड़ लगी रहती है और जनता को हमें जवाब देना पड़ता है । अगर कहीं ऐसी बात अनजाने में मुंह से निकल जाए जो जनता के हित के खिलाफ जाती हो तो हम लोगों पर जो उसका बुरा असर होता है उसको धोने में छः महीने लग जाते हैं । इसके बरअक्स राज्य सभा के मैम्बरों को वही सहूलियतें मिलती हैं जो हमें मिलती हैं । ऐसी अवस्था में अगर वह हाउस एबालिश नहीं होता है तो उनका भत्ता ही घटा दें

[श्री एस० एम० बनर्जी]

तो हम को तसल्ली हो जाए कि कुछ तो आपने किया है । लेकिन सारी सहूलियतें उनको वही मिलती हैं और मैं समझता हूं कि जिम्मेदारी उनकी अपने वोटरों के प्रति कुछ भी नहीं है । वाकई में राज्य सभा को खत्म कर दिया जाना चाहिये ।

कुरप्शन के आधार पर, नोट के आधार पर वोट भी वहां खरीदने की कोशिश होती है और ऐसा हुआ भी है । मैं चाहता हूं कि हम अपने दिलों को टटोल कर पूछें कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है । वहां पर क्या वाकई में नोट के जरिये वोट उन्होंने नहीं खरीदे । क्या ढाई लाख, तीन लाख रुपया जिस की जेब में हो वह राज्य सभा का मैम्बर नहीं बन सकता है डंके की चोट पर ? मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूं । एक मैम्बर जो हमारे क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे राज्य सभा के लिए, उन के बारे में मैंने कहा था कि वह जीतेंगे नहीं । उन्होंने कहा कि मैं हाइएस्ट वोट पोल करूंगा । वाकई में 42 वोट उनको मिल गए । गिन कर उन्होंने बताया कि 42 मिलेंगे और 42 हाइएस्ट मिले । हम लोग दंग रह गए । डैमोक्रेसी किधर जा रही है ।

फिर राज्य सभा बनी रहेगी तो चुनाव में हारने के बाद आदमी एक ही चीज सोचेगा कि कोई न कोई राज्य सभा का मैम्बर रिटायर हो, मैं उसकी जगह आ जाऊं । आपने देखा होगा कि गिद्ध बैठी रहती है और चारों तरफ देखती रहती है कि कोई गाय मरे या कोई दूसरा मरे ताकि उसको वे खा सकें । इसी तरह से राज्य सभा की सीट के पीछे जब भी कोई खाली होती है दस या बीस लोग रोजाना लगे रहते हैं । वे यही प्रार्थना करते रहते हैं कि कोई रिटायर हो जाए या भगवान किसी को ले जाए ताकि मैं हमें मौका मिल सके ।

इसके जो कानूनी पहलू हैं उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं । सोमनाथ चटर्जी उन पर प्रकाश डालेंगे और उनको आर्गू करेंगे । हो सकता है कि इसकी जरूरत हो । लेकिन क्या आज हिन्दुस्तान इस लग्जरी को एफोर्ड कर सकता है, यह मैं आप से पूछना चाहता हूं ? यह एक लग्जरी है । इंग्लैंड में हाउस आफ कामंज और हाउस आफ लार्ड्ज हो सकते हैं, सोवियत यूनियन में भी इसी तरह से दो हाउसिस हो सकते हैं । लेकिन यहां क्या वाकई में इसकी जरूरत है, यह आपको देखना पड़ेगा । आज हर तरफ इकोनोमी करने की हवा चल रही है, क्लास 4 की पोस्ट्स को एबाशिल किया जा रहा है, चपड़ासियों की पोस्ट्स को एबालिश किया जा रहा है, बजट घटाने की कोशिशें हो रही हैं, लोगों से कहा जाता है कि कम खाएं और अगर कम भी नहीं मिलता है खाने के लिए तो गम खाए और उस सब के बाद भी कहा जाए कि राज्य सभा रखेंगे तो यह समझ में आने वाली बात नहीं है । मैं मिश्र जी की तारीफ करता हूं कि उन्होंने बड़ी हिम्मत से काम लिया है और इस प्रस्ताव को यहां पेश किया है । मुझे मालूम है कि सरकार इसको मानेगी नहीं । लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि कम से कम इस पर वह सोचे तो सही । कांग्रेसी होने के नाते उन्होंने कहा है कि गांधी जी के आदर्शों को फिर से जिन्दा करने की कोशिश होनी चाहिये और ऐसी कोशिश उन्होंने की है । जो दलीलें दी हैं उनके बारे में ज्यादा नहीं कहना है । एक ही बात मुझे कहनी है कि अगर राज्य सभा हटा दी जाए तो देश का कोई नुकसान नहीं होगा और प्रजातांत्रिक उसूलों का भी कोई नुकसान नहीं होगा । वे मैम्बर जो लोक सभा में जीत कर आने की कोशिश नहीं करेंगे या जो डिफीटिड पालिटिशयंज होंगे वे इसी इंतजार में रहेंगे कि किसी तरह से वे राज्य सभा में आ जाएं । यह गलत है, यह हमारे सिद्धान्तों के खिलाफ है । लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबालिश जब हमने किया था तो कुछ लोगों ने उसका विरोध किया था लेकिन आम तरीके से

लोगों ने उसका स्वागत ही किया था । लोगों ने कहा था कि सही फैसला किया गया है । उसी तरह से अगर आज कोई खास कानूनी अड़चन न हो संवैधानिक अड़चन नहो तो कम से कम सरकार संजीदगी के साथ इसको सोचे और सोच समझ कर फैसला करे कि आज जबकि हिन्दुस्तान में भुखमरी है , बेकारी का दौर दौरा है, बेकारी से तंग आ कर लोग आत्म हत्या तक करने के लिए तैयार हो रहे हैं और कर रहे हैं, ऐसे मौके पर हम राज्य सभा रखें या न रखें, जो नोट के जरिये वोट खरीदे जा रहे हैं, उस को बन्द करे या न, करे इस पर हमको संजीदगी के साथ सोचना होगा। एक तरफ तो इसको बन्द करने की कोशिश होनी चाहिए और दूसरी तरफ अखराजात को भी कम करने की कोशिश होनी चाहिए । यह मैं चाहता हूं । इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव की पूरी ताइद करता हूं ।

17 hrs.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY (Nizamabad): Mr. Chairman, I rise to oppose the Resolution moved by Shri Bibhuti Mishra. He is a great freedom fighter and I have great respect for him. But, unfortunately, I cannot support the Resolution he has moved in this House. Similarly, I oppose the ideas expressed by my hon. friend, Shri S. M. Banerjee.

The hon. Member repeatedly referred to Rajya Sabha as superfluous, the fifth wheel and so on. The Rajya Sabha is not identical to the House of Lords. The membership of the House of Lords is hereditary, whereas in the case of the Rajya Sabha there is election every two years. One-third of the members retire every second year.

Shri Bibhuti Mishra mentioned just now that the expenditure on Rajya Sabha is over Rs. 1 crore. Ours is a big country with a budget of over Rs. 5,000 crores. If in such a big country with such a big budget, we cannot afford to spend Rs. 1 crores for the maintenance of Rajya Sabha, I feel sorry for it.

Let us not forget that the Rajya Sabha is a revising chamber. We are all directly elected by the people and we are subject to political pressures. Then, sometimes in a hurry we pass measures which may have some lacuna which require second thought. So, it is very much necessary to have a second chamber, which will be a revising chamber. It will be able to consider at leisure what we have passed in a hurry. For a country with a population of 56 crores, to say that one House is enough is not correct.

Shri Bibhuti Mishra mentioned that Rajya Sabha vetoed the Bill on the abolition of privy purse and other privileges. It was a blessing in disguise. Because of that we went to the pools and got a big majority. In that way, the Rajya Sabha did signal service to the country. The slender majority was converted into a big majority.

Shri S. M. Banerjee said that it is very easy to get a seat in the Rajya Sabha because only 42 MLAs have to vote and members can be purchased. I am sorry he said that membership of the Rajya Sabha, or the vote of the MLA, can be bought. If the MLAs can be bought, is it humanly impossible that MPs can also be bought? So, let us not make such charges.

After all, we are, rather we have been depending on the MLAs for our election. Until the 1971 elections the MPs were depending on the MLAs for their election. Only in 1971 the two elections were separated. If Shri S. M. Banerjee was elected to the Lok Sabha four times, three times he was elected with the help of the MLAs. So, let him not say that those MLAs can be purchased.

Then it is said that people belonging to monopoly groups will get elected to the Rajya Sabha. What is the harm? As long as you do not do away with them, as is happening in the Communist countries, they should be allowed to come. Under our Constitution, any person who is thirty years

[Shri M. Ram Gopal Reddy]

of age and of sound mind and satisfying some other qualifications can get elected to Rajya Sabha. Several of our opposition members can contest for the Rajya Sabha elections. Like that, if Birla or Tata or somebody else gets elected to Rajya Sabha, there is no harm. We can face him. How many Birlas and Tatas are there? Every time, they go on repeating four or five names. If the Opposition parties are so much afraid of them, I am really sorry for them.

Then, Shri S. M. Banerjee said that Mahatma Gandhi never became a Member of Parliament or Rajya Sabha or any such thing. I want to say that Carl Marx never became a Member of Parliament or anything like that. The big people are only there to guide the nation and guide the destinies of the people. You cannot think of Mahatma Gandhi being a Member of Parliament. Mahatma Gandhi is in his own place and his ideals are before the country.

श्री विभूति मिश्र : गांधीजी ने फ़ेडरल स्ट्रक्चर कमेटी में बयान दिया था कि हिन्दुस्तान का कैसा ढांचा रहेगा। पार्लियामेंट में उन के आने का सवाल ही नहीं है।

SHRI M. RAM GOPAL REDDY: Mahatma Gandhi was too great a man and an idealist. He has laid down great principles before the country. We cannot translate every word of what he has said. That is an ideal. We have to go towards that end. To demand the abolition of Rajya Sabha is not proper. Moreover, why should we think of Birlas and Tatas only being elected to Rajya Sabha? Why should we not think of people like Shri Bhupesh Gupta and others? Such eminent people are in Rajya Sabha and they are rendering a good service to the nation.

Moreover, some of our Bills have come back from Rajya Sabha with certain amendments and we have accepted those amendments. Therefore, to say that they are not contributing anything towards parliamentary democracy is not correct. Previously, the princes also had one chamber and so also the House of Lords. But that cannot be applied to our country. We should not treat the Members of Rajya Sabha as Members of the House of Lords or some such thing or the chamber of princes. We should not try to insult our own men who are elected to Rajya Sabha.

As regards the point that defeated persons are given berths in Rajya Sabha, that is a very rare thing. When it is absolutely necessary, they should be sent to Rajya Sabha so that we may have advantage of their experience. Several times, in some countries, when a great leader is defeated at the polls, next time, he is given a chance and he gets elected and guides the destinies of the nation. Here, I want to give one example of Shri Morarji Desai. He was defeated but he was made the Chief Minister. Next time, he got himself elected. There are some persons who are indispensable to our country at one time. That is why we have to provide the Upper House so that the best men who sometimes, unfortunately, get defeated are not discarded and the country should not be deprived of their services to the nation.

With these words, I oppose the Resolution in all its aspects.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Burdwan): Mr. Chairman, Sir, the Resolution moved by the hon. Member Shri Bibhuti Mishra, is for the total abolition of Rajya Sabha. So far as I am concerned and the party for whom I am speaking, we do not support the Resolution in the way in which it has been framed. If the Resolution was intended to suggest methods of reform and change in the constitution of Rajya Sabha, then, certainly, we would have come forward in support of the Resolution.

So far as this country is concerned, this is a matter of constitutional importance, not a matter to be looked at from the point of view of party politics. The question is that so far as this country is concerned, we have evolved a constitution where under Art. 1 itself, this country, India, that is Bharat shall be a union of States. That means that our founding fathers have framed a federal constitution for this country and the main characteristic of a federal constitution is the bicameral legislature. That is to say, it is also called a bicameral constitutionalism as Dicay, a very well-known author, though he belonged to a University which we may not all like, says:

> "A federal state is a political contrivance intended to reconcile national unity and powers with maintenance of States' rights. The indispensable quality of a federal state is the distribution of the powers of government between the federating authority and the federating units."

That is why we find in all the federal States in the world from USSR to USA, Italy and Australia wherever a federal constitution is evolved, a bicameral legislature is a must, for the simple reason that the States, apart from the people as such, should have a representation in the formulation of the legislative processes in the country and that is why what we feel is that what should have been incorporated in the Constitution is not only that the States should have representation for a proper development of a federal structure, but it was essential that all the States should be given equal representation. That is what is done in USSR. That is what is done in the USA. That is what is done in Australia. Canada, of course, is different but these three very well-known federal constitutions lay down as a question of constitutional requirement that all States must have equal representation in the Council of States. Unfortunately, in our constitution I find it has set out a list in the Appendix where different representations are given but I do not find any basis for that. Population cannot be the basis. We have all agree to join in the Indian Union for the upliftment not only of the Indian Union as such, but for the federating States as well. We want an integrated development not only of the country but of the States as well. Therefore, the States must have a feeling that they belong to a federation and there is no discrimination between one State and another. There should be equal representation. Therefore, if the hon. Member had come forward with such a proposal, we would have certainly supported it.

The other aspect which should have been taken into consideration, we feel, when the constitution was evolved is namely: how do you get members elected or selected for the purpose of the Council of States? What has been evolved is a system of indirect election and it has got its attendant misuses. The hon. Members on the other side, the hon. mover and Shri S. M. Banerjee, both referred to that, that this is being abused or misused and discredited politicians or defeated politicians or some persons who can afford to purchase 42 or 43 people, they can get this selection. This sort of malpractices has gone into or crept into the system because of the fact that indirect election has been provided. Why not have a direct election? That will be our proposal also. Let there be a direct election to the Council of States. Depending on the number of members we select for each State, we should have equal representation. This is the same principle which has been followed in the Soviet Russia and also in the United States of America. Though they have different types of economic policy and different types of Government altogether, but so far as the federal structure is concerned, both of them follow the same pattern, namely, direct election to the Council of States from the States but having equal representation for all the States. Since we have accepted this

[Shri Som Nath Chatterjee]

federal structure, we feel that it is essential that there should be a second chamber. It is necessary not only for the purpose of providing checks and balances, but for the purpose of the proper functioning of the respective States in regard to the legislative processes of the country.

17.16 hrs.

[SHRI K. N. TIWARY *in the Chair*]

We make a distinction in the case of West Bengal where with unanimous support we abolished the Council, that is, the Upper House in the West Bengal Legislature. Why? Because there is no question of West Bengal, being a province, having a sort of federal structure there. The West Bengal Council was not serving any useful purpose at all, except what we felt and what we realised often, namely difficulties in the proper functioning of the Lower House.

SHRI VASANT SATHE (Akola): Are you suggesting direct election by the people? It will be redundant and duplication.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: My hon. Member knows the method of choosing so far as representation of States is concerned. Look at the Constitution. States are represented by the method of selection provided therein. A person who may not belong to that State cannot represent that State in the Council of States. I am sure you are aware of that position. In the Federal Structure, the second chamber should be so arranged that it embodies the federal principles. That is applicable to all the States that are forming the federation. States should be represented in it. There are three well-known principles involved here, as every student of political history will be aware of. The first is the federal functioning, that is to say, to give proper representation to the units of the federation, to offer proper representation to the States in the National Legislature. The second is the revising functions and the third is the initiation of legislation.

We felt that so far as the powers of legislative revision is concerned, it should be coordinated with the powers of the lower House. Our Constitution makers have given a position of eminence to the Council of States. Please look at Article 249 of the Constitution. According to Article 249, if the Council of States decides that Parliament can legislate on a matter which admittedly belongs to the State's jurisdiction, than such legislation can be undertaken in our House. Certain matters are in the State list; only States can legislate; but even then, if the Council of State by a resolution decide in this manner, then such legislation can be undertaken here. Then only Parliament gets the power to legislate on a subject which falls on the State list.

In Article 312 of the Constitution, it is provided that All-India services can be formed. Unless the Council of State passes a Resolution giving such an authority, the Parliament of India cannot constitute such an all-India service. This is the position.

Now the question arises as to why the constitution makers gave such power of eminence at least on two vital issues to the Council of States. This is because the Constitution has recognised the federal structure of the country. The federating units must have a sense of belonging to that unit and they must have proper the national legislature. So far as the method of election is concerned, in the USA they are chosen by direct election. In the Soviet Russia they are having direct method of election. There are many such instances. The only instance where we find indirect method of choosing is in respect of the House of Lords. Why should we try to form that the constitution of the Council of States or second Chamber be either on the basis of heredity or on the basis of vested interests. Take away all those opportunities. Don't make it open for any abuse or mis-use.

Therefore, Sir, we cannot support the Resolution in the form it has been framed. On the other hand a time has come when serious thought should be given as to how the defects which have been found out in the functioning of the Rajya Sabha because of its constitution or because of the unequal representation in the constitution of Rajya Sabha can be removed and how a better and more coordinated constitution be there so that all the participating States can have a real voice and equal voice in the deliberations of the Council of States. Why should a particular State have five members and another 30 or 40 members? What is the basis of it? They have not joined the Union of India because of their size but because they want to participate and become a member of the union of States. They have their own identity as a federating State itself. Then why do you have different types of membership for which there is no rationale. Therefore, if I may submit, the following proposal should be seriously considered and, if possible, accepted. There should be equal representation of each State and that the Member should be elected from and in the State and free from federating control. As one of the very well-known author has said:

> "The more the choosing of the second Chamber is out of popular control, the more it tends to become detached from realities of body politic."

Therefore, Sir, let us remove this defect and try to make Council of States more a symbol of a proper federal structure in this country and a useful instrument for implementation of the federal structure in this country.

SHRI D. N. TIWARY (Gopalganj): Mr. Chairman, at least on one point I am in agreement with the previous speaker that the federal structure of our country requires second Chamber here. The method of selection may differ. I also differ from him in what he has enumerated as the method of selection. Why Assembly should be given the right to choose is dependent on one point. In different States different parties come into power. Because there are local elections with limited areas the voters, the government and the Assembly members representing the party at that time may elect the representatives here in the Rajya Sabha. If other methods are selected that party may not have the representation here. I am very sorry to differ with my hon. friend, Shri Bibhuti Mishra, on this matter. He has brought the name of Gandhiji. I request him and all our friends not to drag Gandhiji in these matters. We are not following the principles of Gandhiji here. We are not accepting many of his instructions that he gave in his lifetime for conducting our government. Why drag his name in one matter? So far as he has quoted Pandit Jawahar Lal Nehru, at the time the Constitution was passed Pandit Jawahar Lal Nehru was *sarve sarva* of this country. He could have done what ever he wished. But in his wisdom he thought there should be a second Chamber in India. I cannot say the reasons which dictated him to accept this framework. In his lifetime, he never tried to abolish the Rajya Sabha. So to quote Pandit Nehru in this context is perhaps useless and would not cut much ice.

Shri Bibhuti Mishra has given three or four reasons for abolition. One is expenditure. The other is bickerings between the two chambers. The third is its uselessness. As for expenditure, nearly a crore of rupees is spent on the upper chamber. What is that expenditure? Daily we are seeing that our estimates go higher and higher. The Gandak project started with an estimate of Rs. 50 crores; it has gone up to Rs. 152 crores, more than three times. We are not caring to control this expenditure but we are caring very much to control the expenditure or

[Shri D. N. Tiwary]

cut the expenditure of just a crore of rupees. If the chamber is useless and does not serve any purpose, it may be abolished, but not on the ground of expenditure.

Then we have seen that we pass many Bills and send them to the Rajya Sabha. There some amendments are made and sent over here which are readily accepted by us. Only once we differed, in regard to the Dowry Bill when there was a joint session. Otherwise, we have never differed and we have accepted their amendments readily and those Bills have become Acts only after the acceptance of those amendments. I think more than 25 per cent of the Bills have been accepted with such amendments. So they are serving a purpose in correcting our omissions or mistakes. It is a very good thing that there is one chamber to take care of the shortcomings or mistakes that we commit in this Chamber in passing Bills.

He also said that the other House serves no useful purpose. The idea of a second chamber was to represent the States. Under our federal structure, the States should send their representatives to protect their interests, to speak on their behalf. We are all elected from different States, but we are not representatives of the Governments of those States. We repruesent the people. We may differ from or State Governments; we may put forth some other view than what those Governments want us to do. But the Rajya Sabha members are bound to project the views of their respective Governments. The election may be by any method that may be decided or settled. But they should project the views of the Governments of their States. If anybody says that the Members of Lok Sabha will represent their view, it is wrong. We, the members of Lok Sabha, have independent views and we represent the people. We may think in one way and the Governments of the States may think in another.

Pandit Mishra cited one instance where the progress of a progressive Bill was stopped due to the vote of the Rajya Sabha. It was not so. It was because a party which called itself progressive, that is the Congress(O), came in the way. If it had voted for that Bill, the Bill would have been passed with the requisite majority. But as the saying goes, it was a case of cutting the nose to spite the face, on their part. They did this. It was not because the Rajya Sabha came in the way and blocked this Bill. Supposing the Communist party becomes reactionary, what can we do? They can stop any progressive measure in the Rajya Sabha if they like to. So, it is not an argument to say that because the Bill relating to the princes was defeated there, the Rajya Sabha should be abolished.

One thing more. There may be a faulty election or selection of candidates to the Rajya Sabha, but the Rajya Sabha is meant to give a second look on the Bills that we pass, and so mature men should be selected. There are no two opinions on that. If that is not done, that is the fault of the different parties, not the fault of the system, because we select such candidates who are very raw, who have no experience and therefore such things happen. If the different parties select mature men for the Rajya Sabha and get them elected, then it will be all right. I do not think that going to Rajya Sabha debars any man from the public image. There are workers, as Mr. Bibhuti Mishra himself said, who are not in anyway less patriotic, less progressive, than us. So, at this stage, to raise this question of the abolition of the Rajya Sabha, I think, is premature, and if at all anything is to be done, what needs to be done is to think about the way of the selection of members to the Rajya Sabha. We have got indirect election in our Congress party. The ordinary members of the party elect the delegates and those delegates elect the representatives of the AICC. Shri Mishra is also represented there

through indirect election. Even in our party there are indirect elections for the AICC members. So, there is no harm if the elected representatives in the Assembly elect the Rajya Sabha members. Somebody may be corrupt, and somebody amongst us here may also be corrupt, but that is another thing. That is no ground for saying that the members of Legislative Assemblies are purchased and corrption increases.

With these words, I oppose the resolution of Shri Bibhuti Mishra.

SHRI SEZHIYAN (Kumbakonam): Mr. Chairman, Sir, I rise to totally oppose the resolution before this House, brought forward by Shri Bibhuti Mishra. On this resolution, I am fully aware that the discussion that we are having is only of an academic interest. Even if this House passes the resolution, the proposition should be brought forward by a Constitutional amendment and passed by a two-third majority here and sent to the Rajya Sabha and unless they want to commit suicide it will not be passed there. Anyhow, I am clear in my mind that this raises very many fundamental issues of policy in this country.

I am very glad that the discussion that is taking place is on a very high level, on a non-party level, because the two Members who spoke from that side also opposed this measure, and I liked the spirit, because we are having a discussion on the political structure of a federal country. Every one of us is interested to see how the federation is to be run.

Before I come to the bicameral system of parliamentary government which is essential for the spirit and idea of a federation, I will go through one or two points that have been put forward by Mr. Bibhuti Mishra in favour of the abolition of the Rajya Sabha. It was said that if there is only one chamber, quick decisions could be taken and that if there is another chamber, more money has to be spent and duplication comes in the way, especially when we consider Bills here, say, for five days and the Rajya Sabha there takes another three days. All these arguments may appear to be plausible on the face of it, but there is a price that we have to pay for democracy. When Hitler was in power in Germany, he said the same thing against the British Government. "What these 500 members of Parliament in England do in five days, I do in one hour." If you stretch that argument then 522 Members of the Lok Sabha will be found redundant and 50 Ministers will do. Another stage will come, when even 50 Ministers are not necessary and one person can run the entire country. This kind of argument cannot solve the problems before the country.

Mr. Mishra said that Rajya Sabha Members were being elected indirectly and therefore there was scope for corruption. Another Member from this side said that if one spent Rs. 5 lakhs, one could become a Member of the Rajya Sabha. In this country, we know that sometimes Rs. 15, 17 or even 20 lakhs are spent on elections, bye-election to Parliament even in the case of Assembly election vast amounts are spent. As a true Gandhian, he must first convince his own party members that they should not spend more amount than its prescribed by law. They have themselves accepted that this has been observed more in the breach. There is scope for corruption, but it is not only in the elections to Rajya Sabha but in all the elections. Can this be an argument? Suppose there is an Assembly of 60 persons. If 32 persons are bought, one becomes the Chief Minister. Then you should abolish that system also and the Chief Minister should be elected directly. He referred to the expenditure. An expenditure of one crore of rupees out of five thousand crores, I think, is a small amount. We do not have as much facility as the Senator in the U.S.A. or Members of Parliament in

[Shri Sezhiyan]

other countries have. We work with meagre facilities. He says that this is an expenditure which this country can ill-afford. The same argument can be quoted against us. We are paid Rs. 51 per day, which is much above the average *per capita* income of the vast majority of people in this country, the average *per capita* income in this country per month is Rs. 37. Should we abolish Lok Sabha? He quoted Gandhiji. I do not want to polute that name. In May, 1953, Shri Jawaharlal Nehru said:

> "Each House has full authority to regulate its own procedure within the limits of the Constitution. Neither House, by itself, constituted Parliament; it is the two Houses together-that is the Parliament of India. The constitution treats the two Houses equally except in certain financial matters, which are to be the sole prerogative of the House of people".

So Nehru was clear about the usefulness and importance of Rajya Sabha.

The mover of this motion, if he had gone through the Constitution, would have found that the name Rajya Sabha, so also Lok Sabha, is not there in the Constitution. We gave these names after the Constitution was framed. The Constitution calls it the Council of States. Nowhere in the world has it been so well defined as in our Constitution. In the United States they call it "The Senate"; in the United Kingdom they call it "House of Lords". Here we call it the Council of States Therefore, it is the forum, the highest legislative forum of the country, wherein the units of the federation get representation and, participate. The Council of States has got a place in the federal structure of this country. Tampering with it will be the negation of the very basis of the federation.

One more point is that rightly or wrongly, our Constitution has opted for a federal system. I feel that it is the only thing that could have been done. Historically and geographically, nobody can escape from this idea. Unitary form of Government is ruled out. If you feel that the second chamber is redundant, the same argument can be put forth for the States also. We can abolish all State Legislatures and save more money and we can have only one unit at the Centre which can control them. Whether it is politically possible or not I have got my own doubts. If they feel, let them try that. It has been tried from the days of *Ithikasa* and from the days of Rama and Ravana. Therefore, the very best thing to preserve the democracy is not only to accept the riversities but also to respect that and recognise them. That is what the founding fathers of our Constitution have done; in accepting the diversity in this country, a federal set-up had been recommended.

We, the members of the D.M.K. believe in the federal structure of this country. Whenever we want more powers for the State, I want to make clear, we do not want to weaken the centre. The centre should be strong if not stronger. I feel that if they want more powers let them have them. We want a stronger Centre. At the same time we do not want to burden them with unnecessary matters which could be dealt with at the States level. For example, public health comes under the purview of the States. I want the States to be more responsible and better equipped themselves than what they are to-day. I think that the strong States together will make a strong Centre and make India strong if not stronger. Therefore, when we ask for powers for the States from the Centre, it is not done in a spirit of confrontation but it is asked for with a spirit of co-operation. With that cooperation we want to build this country into a strong one.

Sir, when we speak like this, we are fully aware that the States and the Centre together which go into

the federal set up should have enough resources to meet their expenses. That is the only thing we want. In this case, we want a federal set up which should be healthy. I fully support the view point put forth by Shri Som Nath Chatterjee that in the Council of States, equal representation should be given to all the federating units—whether big or small. In U.S.A. New York State contains millions of people and the State of Navada may have only a few lakhs of people, yet they get equal representation when it comes to the Senate. Equal representation should be given to the Council of States here too.

Finally I want to say one word about the Council of States. This represents the interests of the federating units. If you want to abolish that, it would tantamount to avoiding the very basis of the federal structure in this country. Therefore, I beg Shri Mishra, who is older than I and who should have more wisdom than I, to see that India should be kept as a federating unit wherein everybody should cooperate so as to build a strong India. It is in that spirit that I say that the Council of States should be preserved and in India it is worth keeping.

MR. CHAIRMAN: Shri Ishaque.

SHRI A. K. M. ISHAQUE (Basirhat): Mr. Chairman, Sir, by the time I participate in the discussion, it has become more or less an academic discussion. All the speakers have spoken for and against this Resolution from this side as well as from the other side. But, what amazes me most is the speech of the hon. Member, Shri Som Nath Chatterjee. His was a constructive speech. I was wondering whether a marxist Member could speak like that. He of course made some constructive suggestions. I entirely agree with him when he says that the representation of the States must be uniform. Article 1 says, India shall be a Union of States, but the fourth schedule enumerates the representation of each State. UP has 34 members, West Bengal 16, Jammu and Kashmir 4, Nagaland 1 etc. in the Rajya Sabha. So, the number differs from State to State. So, if Mr. Mishra would have sought an amendment of the fourth schedule of the Constitution, we would have welcomed it. There is no reason or principle why all States should not have equal representation in the Council of States.

Everyone has spoken about the utility of the second chamber. It acts as a check and balance. Particularly with the CPM members who have got a propensity to be irrational and illogical, it may happen that at times this House passes a Bill in great haste and out of mood. If a second chamber is there, it can consider the Bill in the right mood and in the mean time, the mood may settle down and everyone may be able to see reason. Therein lies the utility of the second chamber.

In our Constitution, the Council of States is the only perpetual body. The House of the people can be dissolved. Of course there is no chance of the House of the People being dissolved in the next 20 or 30 years, but the contigency may happen. So, we must have in the country a perpetual body and that is provided by the Council of States.

Mr. Chatterjee, while advocating that the Council of States must have equal representation for all the States, was also suggesting that there should be direct election to it. I oppose it very much. If members are elected to the Council directly, they will demand equal power with the Lok Sabha. There are two different entities. It is a fact of life that there are people in India and it is also a fact of life that there are States in India. In the case of a conflict between the people and the States reason demands that it is the people who must win. So, in case of a tussle between the Lok Sabha—the House of

[Shri A. K. M. Ishaque]

the people—and the Rajya Sabha—the Council of States—it is the Lok Sabha that must win. In case you have direct election to Rajya Sabha, their members will naturally demand equal rights with the Lok Sabha because they are also elected by the people. They are not elected by any *via media* institution. We are elected directly. In case you give Rajya Sabha equal power with the Lok Sabha, there will be a chance of clash between both Houses. Therefore, I oppose the suggestion that there should be any amendment to the Fourth Schedule of the Constitution to make elections to the Rajya Sabha direct. While I congratulate our senior member, Shri Bibhuti Mishra for the spirit in which he has brought this Resolution, I am sorry I cannot support him because in India there is necessity for a bicameral legislature as only in a bicameral legislature we can accommodate the States, whose interests must also be looked into at the same time.

श्री राम रतन शर्मा (बांदा) : सभापति महोदय, राज्यों ने मिल करके संघ शासन की स्थापना की है । सभी राज्य सरकारों ने एक संघ बनाया है और उसी से संघ शासन की संघ स्थापना हुई है । हमारा संविधान संघात्मक है । यह संविधानिक प्रश्न है, इसलिए उन प्राविजन को हमें पुन: देखना होगा जो संविधान में है । जो बहस चल रही है उस में कुछ लोगों ने इन प्राविजंज को खत्म करने की बात कही है और कुछ ने उसका समर्थन किया है । एक बार पुन: आर्टिकल 79 और आर्टिकल 80 आपके सामने रखना चाहता हूं :

"There shall be a Parliament for the Union which shall consist of the President and two Houses to be known respectively as the Council of States and the House of the People.

इस में प्रेजीडेंट के बाद काउंसिल आफ स्टेट्स और उसके बाद हाउस आफ दी पीपल है । काउंसिल आफ स्टेट्स इसलिए है कि जो इकाईयां हैं उन्होंने मिल कर संघ बनाया है, इसलिए काउंसिल उनको रिप्रिजेंट करती है । इस वास्ते उनका रिप्रिजेंटेशन बहुत आवश्यक है ।

आर्टिकल 80 भी देखना बहुत आवश्यक है । काउंसिल आफ स्टेट्स कैसे कांस्टीट्यूट होती है, इसका जिक्र इस में है ।

(1) The Council of States shall consist of—

(a) tweleve members to be nominated by the President in accordance with the provisions of clause (3); and

(b) not more than two hundred and thirtyeight representatives of the States...."

जिस तरह का आधार यहां दिया हुआ है उस तरह से यह बनती है । इस में एक और अच्छी चीज रखी गई है । इस में बहुत से विद्वान आदमियों के लिए स्थान सुरक्षित किए गए हैं :

"(3) The members to be nominated by the President under sub-clause (a) of clause (1) shall consist of persons having special knowledge or practical experience in respect of such matters as the following, namely:—

Literature, science, art and social service."

बहुत सी बातें यहां कही गई हैं । यह कहा गया है कि वे डायरेक्ट इलेक्शन में जीत कर आ सकते हैं । जिस आदमी ने अपने जीवन आर्ट में लगा दिया हो, साइंस में लगा दिया है, दूसरी विद्याओं में लगा दिया हो, जिन्दगी भर रिसर्च करता रहा हो क्या आप समझते हैं कि वह डायरेक्ट इलैक्शन में जीत कर आ सकता है ? साधारण जनता आर्ट और साइंस को समझ ही क्या सकती है ? फिर हमारे देश में शैक्षणिक योग्यता ही आम

लोगों में कितनी है ? इस वास्ते जो यह संविधान में रखा गया है किसी परपज से ही रखा गया है और वह परपज बहुत अच्छा है ? इन विषयों में अगर हम यहां लैजिस्लेट करते हैं, कानून बनाते हैं, साइंस के बारे में बनाते हैं उनके बारे में एक मौका मिलता है उनके यहां होने से रीथिंकिंग का और वे लोग अपने ज्ञान के बल पर सही राय उन विषयों के बारे में दे सकते हैं और उनको ऐसा करने का मौका मिलता है।

अगर राज्य सभा को समाप्त कर दिया जाए जैसा मिश्र जी ने कहा है तो निश्चय ही राज्यों के प्रतिनिधि यहां पर नहीं आयेंगे एक एक जिले के, एक एक निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि ही आएंगे तो – राज्य सरकारों का क्या व्यू है वह हमारे व्यूज से मेल खाता भी है या नहीं खाता है, इसका पता नहीं लग सकेगा। तब राज्यों के प्रतिनिधि नहीं होंगे। इसलिए भी राज्य सभा का रहना बहुत जरूरी है। लोक सभा किसी बिल को जल्दी में पास कर सकती है। उस पर चैक रखने के लिए ताकि बाद में परेशानी न हों, विचारों के प्रवाह में बह कर हम जल्दी में काम न कर बैठें, उस पर चैक रखने के लिए भी राज्य सभा की आवश्यकता है।

मिश्र जी ने प्रस्ताव को पेश करते हुए जो कुछ कहा है उसको मैंने बहुत ध्यान से सुना है। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि पूरी तरह से सोच विचार करने के बाद वह इस बिल को यहां नहीं लाए हैं। वह बहुत योग्य हैं, वृद्ध हैं और हर तरह से आगे हैं। इस में कुछ खर्चा अधिक हो जाता है इसलिए वह इसको खत्म करने के पक्ष में हैं, ऐसा प्रतीत होता है। उन्होंने गांधी जी का उदाहरण भी दिया है। इसके बारे में बहुत से माननीय सदस्य कह चुके हैं। मैं उन बातों को दौहराना नहीं चाहता हूं। नेहरू जी का हवाला भी उन्होंने दिया है। लेकिन नेहरू जी कांस्टिट्युएंट असैम्बली के मैम्बर थे। अगर वह इसको नहीं चाहते थे तो संविधान में इसको स्थान न देते और इसलिए मना कर सकते थे उनका व्यक्तित्व, उनकी तपस्या अंतर त्याग ऐसे थे कि उनके सामने किसी की हिम्मत नहीं पड़ सकती थी कि न कर सके। जिस तरह की सरकार वह चाहते देश में लाते। यह कहना कि नेहरू जी नहीं चाहते थे, ठीक नहीं है। उन्होंने किसी संदर्भ में ऐसी बात कह दी होगी। मैं चाहता हूं कि उनके पूरे भाषण को पढ़ा जाए। अगर ऐसा किया गया तो मेरा ख्याल है कि आप इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि नेहरू जी यही चाहते थे कि संघात्मक पद्धति से देश का शासन चले। इसलिए इसको संविधान में स्थान दिया गया है।

18.02 hrs.

यह भी कहा गया है कि जो चुनाव में हार जाते हैं राजनीतिज्ञ उनको ले आया जाता है। मैं कहुंगा कि यह तो पार्टियों की गलती है, स्टेट्स की गलती है। अगर कोई स्टेट चाहती है कि इस आदमी को वह अपना प्रतिनिधि बना कर भेजे तो इससे आपको क्या नुक्सान है। आपको इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिये। अगर राज्य समझता है कि फलां आदमी उसको बेहतर रिप्रिजैंट करेगा तो चाहे वह हार गया हो जिसके पचासों कारण हो सकते है, तो इस पर किसी को एतराज नहीं करना चाहिये आपने यह भी कहा है कि वोट खरीद लिए जाते हैं। लेकिन क्या लोक सभा के वास्ते इलैक्शन में पचासों अर्जियां रोजना इसके बारे में इलैक्शन कमिशन के पास नहीं पहुंचाती है ? यह कोई छिपी बात नहीं है। लोग वोट खरीदते हैं और इस सदन में आते हैं। यह तो पद्धति की ग़लती है और हम सब

[श्री राम रतन शर्मा]

को इस में सुधार करने का प्रयत्न करना चाहिए। माननीय सदस्य का दल शासन में है। इसलिए वह इस में सुधार करने के लिए बेहतर स्थिति में हैं। उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस के जो भी कैंडीडेट चुनाव लड़ें, वह निर्धारित लिमिट के अन्दर पैसा खर्च करें। इस बारे में जो आरोप लगाये जाते हैं, वे उस दल के कडीडेट्स के बारे में ही अधिक लगाये जाते हैं।

माननीय सदस्य ने कहा है कि राज्य सभा पर 114 लाख रुपये खर्च होते हैं। मैं समझता हूं कि देशहित में यह कोई बड़ा खर्च नहीं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा संघात्मक संविधान बना रहे, तो देशहित में जितना भी खर्च करना पड़े, वह कम है। इसलिए इस विषय में खर्च का सवाल लाने की आवश्यकता नहीं है।

माननीय सदस्य ने कहा है कि राज्य सभा की उपयोगिता नहीं है और सरकार को सुबुद्धि आनी चाहिए। सरकार को सुबुद्धि कभी नहीं आयेगी।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अब खत्म करें।

श्री राम रतन शर्मा : इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

18.02 hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

TWENTY-EIGHTH REPORT

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI K. RAGHU RAMAIAH): I beg to present the Twenty-eighth Report of the Business Advisory Committee.

18.03 hrs.

DISCUSSION RE: AGITATION BY DOCTORS IN DELHI HOSPITALS

MR. CHAIRMAN: Now, we take up the discussion under Rule 193.

Prof. Madhu Dandavate.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): The subject matter of the discussion is not merely of an academic importance, but it is a vital matter to us all because we are greatly concerned with the interests of the Medicos on the one side and the health and hygiene of the capital of the country on the other. The threatened strike which is likely to affect five prominent hospitals in this city is a very grave matter and I think with a constructive mind we must approach the problem and see that on the one side, the largest area of agreement is arrived and at the same time, the health and hygiene of this city is ensured.

Very often a criticism is heard against the Medicos that these medical graduates are well-placed in life and they come from a better strata of society and that compared to the emoluments which other sectors of our society get, their emoluments are much better and, therefore, why such sections of the society should hold the society to ransom and resort to actions like strike?

It is a matter of prid that I had been a University teacher and I had tried to find out what qualitative changes are taking place in the last few years as far as the composition of students taking up the professional courses are concerned. There was a time in this country when only sons and daughters of the aristocratic families could take up the professional education. But, thanks to the gradual democratisation of the educational system in our country, even the sweepers' families throw up doctors and engineers and, therefore, the entire compositi n of the students joining professional courses is undergoing a vast change and even students from the lower strata of our society manage to get into these professional courses. I know a number of families who by drawing loans to a very great extent send their children to the medical